SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Stop this odd-even and road rationing, otherwise, this type of arrangement will damage the image of the nation. ...(*Interruptions*)... They can take the guidance from the Union Government. Thank you very much.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Plight of displaced families in Jharkhand due to industrialisation

श्री संजीव कुमार (झारखंड): महोदय, विस्थापन झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण झारखंड के संथाल आदिवासी एवं मूलवासी तबाह होने के कगार पर है। कई दशकों से औद्योगिकीरण, कोयला एवं खनिज खनन, डैम बनाने, power plant लगाने इत्यादि के नाम पर झारखंड में हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण होता चला आ रहा है एवं रय्यतों को जमीन के बदले नौकरी एवं मुआवजे के नाम पर ठगी एवं धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। फर्जी लोगों को नौकरी एवं मुआवजे का फायदा दिया गया है, जबकि रय्यत ठके जाते रहे हैं। जमीन अधिग्रहण कानून का बराबर दुरुपयोग होता रहा है। जहां जरूरत नहीं है या जरूरत से ज्यादा जमीन है, विभिन्न सरकारी कम्पनियों द्वारा दशकों के रय्यतों की जमीन का अधिग्रहण किए जाने का खेल कभी नहीं रुका और झारखंड का जल, जंगल, जमीन तबाह होता रहा, लोग विस्थापित होते रहे। आज आलम यह है कि लाखों लाख विस्थापित जो बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एनटीपीसी, एमपीएल, डीबीसी आदि संस्थाओं द्वारा ठगे गए हैं, उसके विरोध में पूरे झारखंड में आंदोलन जारी है। धनबाद के बलियापुर के सीमापाथर गांव में डीबीसी के खिलाफ विस्थापित लोग हजारों की संख्या में करीब महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके संबंध में मैं सदन को पिछले सत्र में अवगत करा चुका हूं। अब वहां सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं।

महोदय, मैं इस सदन में संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकार को झारखंड के सभी विस्थापितों की समस्याओं को समझकर उनका शीघ्र समाधान करना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि झारखंड के सभी विस्थापित आंदोलनकारी एक बैनर के तले आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने और उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

महोदय, दूसरी बात जो मैं सदन को बताना चाहता हूं वह यह है कि हाल ही में राज्य सरकार ने जिस स्थानीय नीति की घोषणा की है, वह झारखंड में विस्थापित समस्या को बढ़ावा देगी और राज्य के संथाल आदिवासी एवं मूलवासी तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे, उनके बच्चों को राज्य में छोटी सी नौकरी के लिए भी महरूम होना पड़ेगा। इन लोगों का जल, जंगल, जमीन, जो औद्योगिकीकरण के नाम पर बरबाद होता आया है, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सरकार जान-बूझकर इस नीति को लागू कर रही है, ताकि राजनीतिक फायदा उठाकर संथाल आदिवासी एवं मूलवासी को नौकरी एवं उनके अन्य अधिकारों से वंचित कर उन्हें राज्य से पालयन करने को मजबूर किया जा सके, क्योंकि इन्हीं सब गलत नीतियों के कारण अब तक झारखंड से करीब एक-तिहाई हिस्सा दूसरे राज्यों में जा चुका है जिनकी हालत दूसरे राज्यों में जानवर से बदतर है।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इस गलत नीति को लागू होने से रोके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

†**جناب غلام رسول بلیاوی** (بہار): مہودے، میں مانئے سدسئے کے وکتوئے سے خود کو سمبدّھ کرتا ہوں۔

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Unilateral decision of the Government in reducing interest rate on Employees Provident Fund

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. Finally, after three days, I got a chance to speak because of ongoing pandemonium. ...(*Interruptions*)... There were more spoilsports than business transacted. That is the ultimate tragedy in this temple of Parliament. Anyway, Sir, I rise to draw the attention of the Government to the unilateral, undemocratic action by the Finance Ministry in unilaterally reducing the rate of interest on the Employees Provident Fund, completely ignoring the unanimous decision of the tripartite body of EPFO, of which no less than a person like the Union Labour Minister is the Chairman. That Committee

† Transliteration in Urdu script.